मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- मोदी का नया झुनझुना–अगले ओलम्पिक में पदक 3
- वोट के बदले प्रवचन सुनिए...टूटी सड़क पर चलिए
- विधानसभा और संसद में मुनियों के प्रवचन 4
- जेंडर बजट के बिना बनते जेंडर चैंपियन
- मनु संहिता ही ठीक थी, उसे लागू किया जाए, यही सर्वोत्तम मार्ग होगा: तरूण सागर 5
- हाईकोर्ट से भी इन्स्पेक्टर अमित को जमानत नहीं 8
- सरपंच बने हैं तो लूटमार करने से क्या डर

वर्ष 29 अंक 20 फरीदाबाद, वीरवार 1-15 सितम्बर 2016 फोन : - 9999595632 ₹ 2

दावा हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने का चल नहीं पा रहे मौजूदा चार भी

झूठ बोलने में विशेष महारत रखने वाली भाजपा के जुमलेबाज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हर महीने में चार बार यह दावा करने से नहीं चूकते कि वे राज्य के प्रत्येक ज़िले में मैडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। राज्य में कुल 21 ज़िले हैं। इनमें रोहतक, खानपुर, मेवात के मेडिकल कॉलेज हरियाणा सरकार के हैं जबकि अग्रोहा वाला अर्द्धसरकारी है। फ़रीदाबाद के ईएसआईसी कॉलेज से राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहीं। करनाल स्थित कल्पना चावला कॉलेज गत 4-5 सालों से 'बन' रहा है और आगामी कई सालों तक बनते रहने की सम्भावना है। खानपुर व मेवात के मेडिकल कॉलेज भी केन्द्र सरकार ने बना कर हरियाणा सरकार को दे दिये लेकिन हरियाणा सरकार के पास इन्हें चलाने को पर्याप्त बजट ही नहीं है। हरियाणवी कहावत यहां बड़ी सटीक बैठती है-गधी मरी पड़ी स भाड़ा सोनीपत का कर रह्या स।

लाल किले से सबका विकास का है नारा और जमीन पर गरीब पर ही बोझ पड़े सारा : उडीसा में अस्पताल से 12 किलोमीटर तक पत्नी की लाश ढ़ोता आदिवासी लाचार

मज़दूर मोर्चा, चंडीगढ़ ब्यूरो

मेडिकल शिक्षा के लिये हरियाणा सरकार ने 2014-15 में कुल 540 करोड़ खर्च किये थे। यह खर्च उक्त चारों चालू कॉलेजों के अलावा करनाल वाले पर भी किया गया था। वर्ष 2015-16 के लिये प्रस्तावित बजट रखा गया कुल 642 करोड़ जिसे 6 माह बाद संशोधित करके बना दिया 583 करोड़ लेकिन वास्तविक खर्च 540 करोड़ के आसपास ही रहनेवाला है। वर्ष 2016-17 का प्रस्तावित बजट रखा गया है 850 करोड़ का लेकिन जिस हिसाब से सरकार खर्च कर रही है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वास्तविक खर्च 600 करोड़ के आसपास ही रहने वाला है।

समझने वाली बात यह है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में आवश्यक उपकरण आदि तो एक ही बार खरीदे जाते हैं, यदा-कदा ही नये अथवा उन्नत उपकरण खरीदे जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा खर्च होता है वेतन का। यहां डॉक्टरों का वेतन एक से दो लाख और कई बार तो इससे भी अधिक हो सकता है, क्योंकि शासक वर्गों की मूर्खता एवं जनविरोधी नीतियों के चलते डॉक्टरों का भारी अभाव इस देश में बना दिया गया है। डॉक्टरों के अलावा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ़ का वेतन बिल भी काफ़ी होता है। बढ़ती महंगाई पर मिलने वाला भत्ता व वेतन आयोगों द्वारा वेतन निर्धारण का सिलसिला भी चलता रहता है।

इसी तरह खपत होने वाली दवाओं, बिजली, पानी के बिलों में भी लगातार वृद्धि होती रहती है। कुल मिलाकर बिना कुछ किये धरे ही प्रतिवर्ष, किसी भी मेडिकल कॉलेज का खर्च 25 से 30 प्रतिशत तक बढ जाना निश्चित है। ऐसे में सरकार द्वारा बजट को न बढ़ाना उसे घटाने के समान ही होता है। अब घटे बजट में काम चले तो कैसे चले, इसका बेहतरीन उपाय सरकार ने ढूंढ रखे हैं। फ़ैकल्टी डॉक्टरों व अन्य स्टाफ़ के पदों को खाली रख कर वेतन खर्च को घटाया जाय। बढिया, ट्रेंड और ज़िम्मेवारी समझनेवाले पैरामेडिकल स्टाफ़ की जगह अस्थाई एवं ठेकेदारी में गैर ज़िम्मेदार और अनट्रेंड स्टाफ़ को रखा जाय। खपत होने वाले सामान एवं दवा आदि न खरीदी जायें। आवश्यक उपकारण एवं उनमें सुधारों को टालते रहा जाये।

विदित है कि खानपुर और मेवात के मेडिकल कॉलेज में कभी भी फ़ैकल्टी एवं स्टाफ़ पूरा नहीं होता। केवल एमसीआई (मेडिकल काऊंसिल ऑफ़ इन्डिया) के निरीक्षण के समय इधर-उधर से पकड़ कर डॉक्टरों को वहां दिखा कर, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर एमसीआई को धोखा दिया जाता है। पिछले दिनों तो फ़रीदाबाद के बीके अस्पताल से चार विशेषज्ञ डॉक्टारों का अस्थाई रूप से वहां तबादला कर दिया गया था जबकि बीके अस्पताल खुद डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है। उक्त दोनों कॉलेजों के हालात सरकार ने ऐसे बना रखे हैं कि वहां कोई फ़ैकल्टी (डॉक्टर) टिकने को राज़ी नहीं। केवल वही टिकता है जिसे कहीं और नौकरी न मिले।

आखिर सरकारी बजट जाता कहां है ?

हरियाणा का 2016-17 का प्रस्तावित बजट 85000 करोड़ का है। इसमें वह 35000 करोड़ भी शामिल है जो खट्टर सरकार भारत की मोदी सरकार से कर्ज लेवेगी। वर्ष 2014-15 में इस तरह का कर्ज मात्र 10 000 करोड़ ही लिया गया था।

सरकार की फ़िज़ूलखर्चियों एवं घपले घोटालों के विस्तार में न जाकर केवल इतना बता रहे हैं कि बिजली विभाग पर सरकार 16826 करोड़ खर्च करने जा रही है, जबकि इस विभाग का अब तक एकत्रित हो चुका घाटा 30 000 करोड़ के पार जा चुका है। समझने वाली बात यह है कि जिस बिजली व्यापार से सरकार को 20-30 हज़ार करोड़ का मुनाफ़ा होना चाहिये था, उसी विभाग को चलाने के लिये सरकार उक्त रकम खर्च करने जा रही है; यही सरकार नहीं पूर्ववर्ती सभी सरकारें यही करती आई हैं। इसी तर्ज पर सरकार के तमाम व्यवसायिक उपक्रम, हरियाणा रोडवेज तक, भारी घाटे में चलते हैं। इन सब को करदाता के खून-पसीने की कमाई से पूरा किया जाता है। संक्षेप में मुनाफ़ा तो गया ऐसी तैसी में घाटा और जनता के सिर मढा जा रहा है। जाहिर है शासक वर्ग इसे बड़ी बेहरमी से डकार रहा है।

अस्पतालों में डॉक्टर और कॉलेज-स्कूलों में मास्टर भले ही न हों, परन्तु आइएएस व आइपीएस अफ़सरों की भरमार है। हर विभाग में एक-एक चीफ़ सेक्रेट्री तैनात है। कुछ ऐसे भी अफ़सर हैं जो सरकार को पसंद नहीं, उनके लिये कोई काम नहीं रहता उन्हें बैठा कर वेतन दिया जाता है। इस तरह के दर्जनों आइएएस व आइपीएस राज्य में मौजूद हैं। विजिलेंस विभाग में जहां कभी एक ही डीजीपी होता था वहां अब 3 डीजीपी तैनात हैं। जाहिर है इन्हें काम के लिये नहीं केवल बैठा कर वेतन देने के लिये रखा गया है।

लुढकती पढ़ाई चढ़ती फ़ीस

समझा जा सकता है कि राज्य के चार मेडिकल कॉलेज में पढने वाले छात्रों की पढ़ाई कैसी होती होगी और वे कैसे डॉक्टर बन पायेंगे। इसे लेकर छात्रों में भारी रोष पनप रहा है। जले पर नमक छिड़कने की तरह हरियाणा सरकार ने अपने सभी चारों मेडिकल कॉलेज की फ़ीस 56000 वार्षिक से बढ़ा कर पूरी एक लाख कर दी। हॉस्टल आदि व अन्य खर्चे अलग से। यानी ग़रीब तो, चाहे कितना ही प्रतिभाशाली क्यों न हो डॉक्टरी पढ़ ही नहीं सकेगा। इस फ़ीस बढ़ोत्तरी का दुष्प्रभाव रोहतक के 850, खानपुर के 400, मेवात के 300 छात्रों पर तुरन्त प्रभाव से पड़ गया है। अग्रोहा इससे बच गया है क्योंकि वहां पहले से ही फ़ीस 2 लाख है। फ़रीदाबाद का ईएसआईसी वाला मेडिकल कॉलेज हरियाणा सरकार के नियन्त्रण से बाहर है। यहां पहले की तरह 24000 वार्षिक की दर से फ़ीस बनी रहेगी। हां अपनी कंगाली कुछ कम करने के लिये हरियाणा सरकार ने यहां के छात्रों से समय पर रजिस्ट्रेशन न कराने का जबराना लगा कर 5000 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से कुल 5 लाख जरूर वसूल लिये हैं। ईएसआईसी ने यह रकम छात्रों से न लेकर खुद ही वहन कर ली है। इतना ही नहीं प्राइवेट कॉलेजों से रोहतक में इन्टर्नशिप करने वालों को कुछ देने की बजाय उनसे भी एक लाख रुपया सरकार वसूल करेगी जबकि अपने इन्टर्नज़ को 28000 मासिक वेतन सरकार देती है। पता नहीं यह वेतन भी कब बन्द कर दिया जाय।

कहने को हरियाणा सरकार ने रोहतक मेडिकल कॉलेज को विश्व विद्यालय का दर्जा दे रखा है लेकिन इसको चलाने के लिये पर्याप्त बजट नहीं है। करीब 56 साल पुराने इस मेडिकल कॉलेज का स्तर दिन ब दिन बढने के बजाय गिरता जा रहा है। इसके चलते रोहतक व आसपास के जिन सैंकड़ों मरीज़ों का इलाज यहां हो जाना चाहिये था, दिल्ली रैफ़र किये जा रहे हैं। कुल जितना बजट सरकार चारों कॉलेजों पर खर्च कर रही है उतना तो कम से कम रोहतक मेडिकल कॉलेज एवं विश्व विद्यालय को चाहिए। दिल्ली के एम्स का वार्षिक बजट 4000 करोड़ रुपये है। वह

शेष पेज दो पर

चिकित्सा का दिखावा:मरीज को मौत का बुलावा

फ़रीदाबाद (म.मो.) गत सप्ताह गुड़गांव के सरकारी अस्पताल में अपनी मां के साथ इलाज के लिये आई एक 9 वर्षीय बच्ची ने घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद दम तोड़ दिया। डॉक्टर एक था, मरीज अनेक लिहाजा लाइन लम्बी लगी थी। बच्ची को प्यास लगी तो मां पानी लेने चली गयी। इसी बीच बच्ची बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे तुरन्त, पास में ही, आपात कालीन सेवा में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जुमलेबाज मुख्यमंत्री खट्टर सरकार ने अपनी जनविरोधी चिकित्सा नीति एवं कार्यशैली पर पर्दा डालने के लिये तुर्त-फुर्त लीपापोती की कार्यवाही कर डाली। इसके अनुसार बच्चों के उन विशेषज्ञ डॉक्टर साहब का तबादला कर दिया गया जिनके आगे लगी लम्बी लाइन में बच्ची खड़ी थी और एक चपरासी को नौकरी से बरखास्त कर दिया, वह जरूर ठेकेदारी का अस्थाई कर्मचारी होगा। ठेकेदार उसे यहां से कहीं और काम पर लगा देगा। सीएमओ (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) ने झटपट अतिरिक्त काऊंटर खोलने का आश्वासन दे डाला।

सदैव झूठ बोल कर जनता को बहकाने वाली इस सरकार से कोई पूछे कि काऊंटर खोलने की जगह अस्पताल में है कहां और उन पर बैठने वाला स्टाफ़ कहां से आयेगा? बच्चों का एक मात्र विशेषज्ञ डॉक्टर बेचारा जैसे तैसे मरीज़ों की भारी भीड़ को निबटा रहा था, डॉक्टरों की संख्या बढाने की बजाय उस एक डॉक्टर को भी वहां से चलता कर दिया जिसके बदले में लगाने के लिये सरकार के पास कोई ढंग का डॉक्टर है नहीं। गुड़गांव में उक्त घटना होने से थोड़ा हल्ला जरूर मच गया वरना स्थिति न केवल हरियाणा में बल्कि सारे देश में बद से बद्तर होती जा रही है। फ़रीदाबाद का सरकारी बीके अस्पताल भी ऐसी ही किसी घटना का इन्तज़ार कर रहा है।

इस लचर चिकित्सा व्यवस्था की जड़ में सरकार की जनविरोधी नीतियां एव कार्यशैली है। नियमानुसार जीडीपी (सकल घरेलू उत्पादन) का 5 प्रतिशत चिकित्सा सेवाओं पर खर्च होना चाहिये जबकि होता 1.75 प्रतिशत ही है और उसमें से भी करीब एक चौथाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ जाता है। हरियाणा सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं का कुल बजट 2800 करोड़ है जिसमें से करीब 600 करोड़ चिकित्सा शिक्षा पर खर्चने के पश्चात् 2200 करोड़ रुपया चिकित्सा सेवाओं पर खर्च किया जाता है। राज्य की ढाई करोड़ आबादी के लिये यह रकम ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

उक्त राशि को भी सरकार ने मुख्य दो हिस्सों में बाटा है। पहला शहरी, जिस पर सरकार 660 करोड़ खर्च करती है। इसमें तमाम ज़िला एवं तहसील स्तरीय बड़े

शेष पेज दो पर

दोनों समाचारों में दिये गये वर्ष 2016-17 के आंकड़े बजट में प्रस्तावित हैं। वास्तविक खर्च इनसे करीब 10-15 प्रतिशत कम ही होगा। इसके अलावा खर्च होने वाली राशि का 15-20 प्रतिशत घपलों-घोटालों एवं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना इस देश की परम्परा है। सरकार चाहे खट्टरों की हो अथवा हुड्डों व चौटालों की।